कश्मीर में 1953 की स्थिति की बहाली

1177. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कश्मीर में वर्ष 1953 की स्थिति बहाल करने के संबंध में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) और (ख) प्रधानमंत्री ने 4 नवम्बर, 1995 को एक वक्तव्य दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार का यह प्रयास होगा कि वह, संविधान के अंतर्गत ही, राज्य के सभी क्षेत्रों के संदर्भ में लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जम्मू एवं कश्मीर राज्य की स्वायत्तता को दुढ़ृढ़ करें। 1975 में हुए समझौते के सम्पूर्णतया कार्यान्वयन के प्रति सरकार की वचनबद्धता को दुहराया गया और साथ ही यह भी कहा गया कि सरकार को "वजीर-ए-आजम" और "सदर-ए-रियासत" के नामकरण बहाल करने पर कोई आपत्ति नहीं होगी यदि राज्य विधान मंडल, इस प्रयोजनार्थ राज्य के संविधान में संशोधन हेतु कार्रवाई करे।

PAPERS LAID ON THE TABLE

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Now, we take up Papers to be laid on the Table of the House. (*Interruptions*). Kindly let me finish it.

श्री रामगोपाल यादव: हमने सुना है कि सुखराम जी ने इस्तीफा दिया है **(व्यवधान)**

विपक्ष के नेता (श्री सिकन्दर बख्त): सुखराम साहब का इस्तीफा अभी तक नहीं आया **(व्यवधान)**

Report and Accounts (1993-94) of the Council for Advancement of People's Action and Rural Technology, New Delhi and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): Sir, I lay on the Table a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(i) Eighth Annual Report and Accounts of the Council for Advancement of People's Action and Rural Technology, New Delhi, for the year 1993-94, together with the Auditors' Report on the Accounts.

(ii) Review by Government on the working of the above Council.

(iii) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (i) above. [Placed in Library. *See* No. LT-8159 /95]

Proclamation in relation to the State of Uttar Pradesh

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DEPARTMENT OF INDIAN SYSTEMS OF MEDICINE AND HOMOEOPATHY) (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR): Sir, I lay on the Table, under sub-clause (a) of clause (2) of article 213 of the Constitution, read with sub-clause (iv) of clause (c) of the Proclamation, dated the 18th October, 1995 issued by the President in relation to the State of Uttar Pradesh, a copy (in English and Hindi) of the Uttar Pradesh Health Workers and Health Supervisors (Regulation of Pay) (Second) Ordinance 1995 (U.P. Ordinance No. 35 of 1995) [Placed in Library. *See* No. LT-8301 /95]

(i) Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Law (fourth Amendment Ordinance, 1995.

(ii) Notification of the Ministry of Urban Affairs and Employment.